भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2891

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन मिशन

2891. श्री इटेला राजेंदरः

डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रुप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करेगी और यह आसान निर्यात ऋण, सीमा–पार फैक्टरिंग सहायता पाने और एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर–टैरिफ उपायों से निपटने के लिए आसान सुविधा प्रदान करेगा ताकि व्यापार में भी सुधार हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस मिशन के लिए अनुमानित तथा आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय व्यवसायों, विशेषकर एमएसएमई के लिए निर्यात ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके;

(घ) एमएसएमई को उत्पादन बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, जिससे उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े; और

(ङ) क्या निर्यात संवर्धन मिशन के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए वित्तीय संस्थानों, उद्योग निकायों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी, यदि कोई हो, की संभावना तलाशी जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) निर्यात संवर्धन मिशन का नेतृत्व वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है ताकि निर्यात ऋण अभिगम, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता, वैश्विक बाजारों में गैर–प्रशुल्क अवरोधों को दूर करने में एमएसएमई के लिए सहायता और बाजार अभिगम के लिए सहायता को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में, मिशन के तहत स्कीमें परामर्श चरण में हैं, जिसमें संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ विचार–विमर्श शामिल है। उपर्युक्त मंत्रालयों के अलावा, इन परामर्शों में प्रमुख प्रतिभागियों में भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्सिम), भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और विभिन्न उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

*****